

म्पादकीय कहर की बरसात

सिसकियां पिछले साल की लौट आईं, बेरहम बरसात ने दरवाजे पे पुनर्दस्तक दी। खत पुराने भी यही खबर देते रहे, लेकिन दिल्ली ने हमारी एक न सुनी। विध्वंस की परिक्रमा में पूरा हिमाचल, लेकिन शिमला, कुल्हू और मंडी में कहर की बरसात ने मौत का समुद्र बना दिया। आधा दर्जन बादलों का शृंखलाबद्ध होकर फटना, जिन घाटियों, नदी-नालों, घरों, सड़कों, योजनाओं-परियोजनाओं और होटलों से होकर गुजरा है, वहां मौत और विनाश का मंजर देखा नहीं जाता। यहां समेज के अस्तित्व को मिटाने वाली बारिश, बागीपुल पर भारी पड़ने वाला पानी और मंडी के जलबहाव में घर-परिवार को मिटाती बाढ़ का रौद्र रूप बता रहा है कि फिलवक सारा हिमाचल चीख रहा है। बुधवार की रात से निकली बीरवार की चीख समेज के पथरों से लौट कर कानों में शीशा पिघला रही है। कल तक वहां आशियाने थे, आशाएं और बस्ती में मस्ती थी, लेकिन आज न घर बचे, न घर के लोग और न ही धरती का नामोनिशान रहा। करीब साढ़े तीन दर्जन लोगों को निगल कर बारिश सिर्फ छोड़ गई अफसोस, करूर यादें और बीभत्स दृश्य, जहां अब अवशेष रो रहे हैं, 'आखिर कहां गए लोग, क्यों गए लोग।' हादसों का प्रदेश बन गया हिमाचल, यहां बारिश अब मौत की सुपारी लेकर आती है। बागीपुल ने एक दर्जन लाशें देखीं, तो पद्धर के पथरों में लापता हो गए नौ से दस लोग। बादल हमारी योजनाओं, नीतियों और खुदगर्जी के भी फटे हैं। बादल हमें घूर रहे हैं, क्योंकि हम उसके आस्तीन के सांप हैं। उसके रास्तों के व्यवधान हैं हम समेज की बस्ती में मौत का सामान हैं। हम तरकीपसंद हिमाचली नदी-नालों के आसपास विकास का जो मंजर खोज रहे हैं, उसमें कितनी कीलें और कितने विस्फोटक झारदे छुपे हैं कि आज हमारे अस्तित्व के निशान फनां हो रहे हैं। बरसात अब अस्तित्व से लड़ रही है, विकास से लड़ रही है। पंडोह बांध के गेट खोलते हैं, तो मंडी का पंचवक्त्र मंदिर बताता है कि डूबने को अब ईश्वर को भी कोई सहारा नहीं मिल रहा। पहाड़ पर पिछले साल भी कोहराम मचा था। नुकसान के अनुमान में आर्थिकी निकल गई और प्रदेश का वित्तीय घाटा बढ़ गया।

लेकिन केंद्र ने हमारी न फरियाद सुनी और न ही पर्वत को समझने की सुध ली। बादल समुद्र से उठते हैं, तो उनका कद और मद अलग होता है। मैदानों के ऊपर उनकी काया और छाया अलग होती है, लेकिन पहाड़ पर वे अपना ठाँउ, अपना सफर फूल कर जब वजनी होते हैं, तो बारिश का अंतिम चरित्र भयावह हो जाता है। ये जख्म बताते हैं कि बादलों में शैतान छुपा था, लेकिन खंजर में तेरा नाम खुदा था। ये खंजर केंद्र-राज्य की बीच फासलों का है। पहाड़ को न समझने की चुनौती को सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। राज्य विनाश की लहरों को न मापने की गलती कर रहा है, तो केंद्र पहाड़ के आंसू पौछने की मर्यादा भंग कर रहा है। हद तो यह कि बरसात को हिमाचल के महकमे ही हल्के से ले रहे हैं। नदी-नालों के किनारे बढ़ रहे हादसों के बावजूद निर्माण की कोई आचार संहिता लागू नहीं होती। वर्षों पहले से पहली जुलाई से 31 अगस्त तक स्कूली अवकाश निर्धारित थे, लेकिन शिक्षा विभाग का मुख्यालय अपने मौसम खुद तय करके बच्चों के स्कूल पहली अगस्त को खोल देता है। इसी पहली अगस्त की किस्त में ढूबे स्कूल और ढहती इमारतें बता रही हैं कि महकमा कहीं बच्चों की जान से खेल रहा है।



ललित गुरु

भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में अराजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या है? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा? इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्त्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मर्दियों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की हैं हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत

जिलाधिकारी ने स्थाय়
खायी फाइलेरिया की
दबा, दो सितम्बर तक
चलेगा कार्यक्रम

फतेहपुर। भारत को फाईलेरिया मुक्त बनाने के लिए रशीय फाईलेरिया उम्मूलन कार्यक्रम के तहत शनिवार को जनपद में फाईलेरिया उम्मूलन कार्यक्रम हुआ। सरदार बलभूषण थाई पटेल प्रेषागृह में आयोजित कार्यक्रम में आईंडीए अभियान 2024 का जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तखापलट के बाद अस्तित्व में आईं सरकारों ने भारत के लिए उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लाग्भग ऐसी ही स्थितियां चीन और

शुभारम्भ किया। फाइलरिया से बचाव के उपाय के बारे में उहोने जानकारी ली एवं अपनी बातों को साझा किया। इस संबंध में उहोने जानकारी ली तो मालूम हुआ कि यह फाइलरिया उन्मूलन कार्यक्रम 10 अगस्त से 02 सितम्बर 2024 तक चलाया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्वयं फाइलरिया की दवा खाकर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि फाइलरिया की दवा अवश्य खाए, क्योंकि फाइलरिया जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है यह एक लाईलाज बीमारी है, जो मच्छर के काटने से होती है। यह बीमारी आम जनमानस को अपाहिज भी कर सकती है। उहोने कहा कि खाली पेट दवा न खाए, दवा खाने से पहले नाश्ता अवश्य करें। विद्यालय के छात्राओं को कुओआयशा, कुहर्षिता, चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा? इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छावि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश

एक बड़े जनजातीय नर संहार के स्मरण का शोक दिवस

प्रवीण गुगानानी
विदेशी शक्तियां भारतीय समाज
को विखंडित करने हेतु
मूलनिवासी दिवस का उपयोग
कर रही हैं। नौ अगस्त, वस्तुतः
पश्चिमी साप्राञ्यवादियों द्वारा
किये गए बड़े, बर्बर नरसंहार का
दिन है। इस शोक दिवस को
उसी पीड़ित व दमित जनजातीय
समाज द्वारा उत्सव व गौरवदिवस
रूप में मनवा लेने का घड़यन्त्र है
यह! आश्र्वय यह है कि पश्चिम
जगत, झूठे विमर्श गढ़ लेने में
माहिर छदम बुद्धिजिवियों के
भरोसे जनजातीय नरसंहार के इस
दिन को जनजातीय समाज द्वारा
ही गौरवदिवस के रूप में मनवाने
कुचक्र में सफल हो रहा है।
वस्तुतः 9 अगस्त का यह दिन
अमेरिका, जर्मनी, स्पेन सहित
समस्त उन पश्चिमी देशों में वहां
के बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा
पश्चाताप, दुःख व क्षमाप्रार्थना का
दिन होना चाहिए। इस दिन
यूरोपियन आक्रमणकारियों को
उन देशों के मूल निवासियों से
क्षमा मांगनी चाहिए जिन
मूलनिवासियों को उन्होंने
बर्बरतापूर्वक नरसंहार करके उहें
उनके मूलनिवास से खदेड़ दिया
था और नगर छोड़कर सुदूर
जंगलों में बसने को विवश कर
दिया था। पश्चिमी बौद्धिक जगत
का प्रताप देखिये कि हुआ ठीक
इसका उल्टा; उन्होंने इस दिन का
स्वरूप, मंतव्य व आशय समूचा
ही उलटा कर दिया और आश्र्वय
यह कि हम भारतीय भी इस थोथे
विमर्श में फंस गए। इस

वन कंदराओं में रहने वाले जनजातीय बंधुओं ने भी आगे बढ़ाया व नगरीय समाज ने भी। वेदों, शास्त्रों, शिलालेखों, जीवाश्मों, शृणियों, पृथ्वी के सर्वचनात्मक विज्ञान, जेनेटिक अध्ययनों आदि के आधार पर जो तथ्य सामने आते हैं उनके अनुसार पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड पर हुई थी जिसे तब पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया गोंडवाना व लारेशिया को मिलाकर बना था। गोंडवाना लैंड के अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, आस्ट्रेलिया एवं भारतीय प्रायद्वीप में विखंडन के पश्चात यहां के निवासी अपने-अपने क्षेत्र में बंट गए थे। जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर हुआ जो विश्व की प्राचीनतम नदी है।

मध्यप्रदेश के भीम बैठका में पाए गए पच्चीस हजार वर्ष पुराने शैलचित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई, तथा मेहरगढ़ के अलावा कुछ अन्य नृवंशीय एवं पुरातत्वीय प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि, विश्व के प्राचीनतम आदिमानव की कर्मभूमि रही है। यही आदिमानव वैदिक या सनातन संस्कृति के जन्मदाता थे। डॉ. शशिकांत भट्ट की पुस्तक नर्मदा वैली = कल्वर एंड सिविलाइजेशन में, नर्मदा घाटी सभ्यता के विषय में मैं विस्तार से उल्लेख मिलता है। नर्मदा किनारे मानव खोपड़ी का पांच से छः लाख वर्ष पुराना

वीवाशम मिला है जो सनातन धर्म के सर्वाधिक प्राचीन धर्म होने के नकाट्य प्रमाण को वैश्विक पटल खोता है। पौराणिक ग्रंथों में जिस वाकांडे शब्द का प्रयोग मिलता है नमदा संस्कृति की प्राचीनता को प्रकट करता है इन सब तथ्यों पर प्रकाश में यह प्रश्न उपजता है कि अंततः यह मूलनिवासी दिवस मनाने का चलन उपजा त्यों व कहां से ? वस्तुतः यह मूलनिवासी दिवस पश्चिम के ग्रंथों की देन है। कोलंबस दिवस के रूप में भी मनाये जाने वाले दिवस दिन को वस्तुतः अंग्रेजों के अपराध बोध को स्वीकार करने वाले दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका से वहां के मूल निवासियों को अतीव बर्बरता और वृक्ष समाप्त कर देने की कहानी पश्चिमी पश्चात्याप दिवस का राग है मूल निवासी दिवस।

वस्तुतः इस मूलनिवासी फंडे पर आधारित यह नई विभाजनकारी खा एक नए पद्यत्र के तहत भारत में लाई जा रही है जिससे भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज भारत आमाजिक समरसता के नये नायाम गढ़ रहा है व अंग्रेजों व परिवर्तन कुछ भारत विरोधी लतों को रास नहीं आ रहा है। स सकारात्मक परिवर्तन के नातावरण में जहर बोने का कार्य रहते हैं कुछ भारत विरोधी व विभाजनकारी लोग। मूल निवासी दिवस के एजेंडे के पीछे बहुत से ऐसे विदेशी मानसिकता के लोग खड़े हो गये हैं व भारत

के भोले भाले जनजातीय समाज के मन में विभाजन के बीज बोरहे हैं। इस पूरे मामले की जड़ बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के समय दो धर्मों; इस्लाम एवं इसाईयत में उपजी निराशा में व कम्युनिस्टों की सोच में है। इसाईयत व इस्लाम धर्म नहीं अपनानें को लेकर बाबा साहब के विचार सुस्पष्ट रहें हैं, उन्होंने स्वर कहा व लिखा कि उनकं अनुयायी इस्लाम व ईसाईयत से दूर रहें। किंतु आज मूलनिवासी वाद के नाम पर भारत का दलित व जनजातीय समाज एक बड़े ईसाई व इस्लामी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है एक बड़े और एकमुश्त धर्म परिवर्तन की आस में बैठे ईसाई धर्म प्रचारक तब बहुत ही निराश व हताश हो गए थे जब बाबासाहब अम्बेडकर ने किसी भारतीय भूमि पर जर्में व भारतीय दर्शन आधारित धर्म में जानें का निर्णय अपनें अनुयायियों को दिया था। कम्युनिस्ट विचार व ईसाई धर्म के इसी षड्यंत्र का अगला क्रम है मूलनिवासी वाद का जन्म! भारतीय दलितों व आदिवासियों को पश्चिमी अवधारणा से जोड़ने व भारतीय समाज में विभाजन के नए केंद्रों की खोज इस मूलनिवासी वाद के नाम पर प्रारंभ कर दी गई है। इस पश्चिमी षड्यंत्र के कुप्रभाव में आकर कुछ दलित व जनजातीय नेताओं ने यह कहना प्रारंभ किया कि भारत के मूल निवासियों (दलितों) को बाहरी आर्यों ने अपना गुलाम बनाकर यहां हिन्दू वर्ण व्यवस्था को लागू किया। बाबा साहेब अपने लेखन कथित आर्य व जनजातीय संघर्ष की बात को ढूढ़ता से नकारते हैं। बाबासाहब ने लिखा है- आर्य आक्रमण की झूटी कथा पश्चिमी लेखकों द्वारा बनाई गई है जिसके कोई प्रमाण नहीं है। अम्बेडकर जी आगे लिखते हैं कि इस पश्चिमी सिद्धांत का विश्लेषण करनें से मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूँ वह यह है - वेदों में आर्य जातिवाद का उल्लेख नहीं है व वेदों में आर्यों द्वारा दलित व जनजातीय आक्रमण कर विजय प्राप्त करनें का कोई प्रमाण नहीं है।

ये कथित लोग कहते हैं कि वे मूलनिवासी हैं और बाकी सारे लोग विदेशी हैं। वस्तुतः सच्चाई यह है कि भारत में रह रहे सभी मूल भारतीय यहां के मूलनिवासी हैं।

वस्तुतः इस नए षड्यंत्र का सूत्रधार पश्चिमी पूंजीवाद है। अनावश्यक ही यह राग अलापा जाता रहा है कि आर्य बाहर से आये थे। इस भ्रामक अवधारणा ने भारतीय संस्कृति का बड़ा अहित किया है। भारतीय जनमानस में परस्पर द्वेष, आर्य-अनार्य विचार एवं दक्षिण-उत्तर की भावना उत्पन्न करने वाला यह विचार, तात्कालिक राजनैतिक लाभ हेतु विदेशियों एवं विधर्मियों द्वारा योजनाबद्ध प्रचारित किया गया है।

पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी घटयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीर-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांगलादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फँसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था।

जननीतिक अस्थिरता के दौरे से जुर रहा है। हाल ही में यहां एक गार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली चंड सरकार सत्ता से बाहर हो रही। अब यहां चीन समर्थक नपी शर्मा ओली की सरकार है। नोली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस समय भारत और नेपाल के बीच एवं संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 बरकारें बदल चुकी हैं। हालात तेवे बदलाव हैं कि वहां पर कुछ नोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन वेस्टरावादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूतान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ वीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है। भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, नफगानिस्तान, भूटान और गोलंका के बाद अब बांग्लादेश देशों पर चीन का दबदबा है और उसके दबाव में भारत के लिये कभी भी संकट बन सकते हैं। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सरकारी, विवेक एवं समझदारी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पडोसी देशों में उत्पन्न हालातों पर समझ एवं संयम से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तखापलट घटनाओं पर भी उसने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी बात रखी। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सर्वसम्मति बनना जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पडोसी देशों में न मिलना ही उनकी अस्थिरता एवं अराजकता का बड़ा कारण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कर्तव्य नहीं बननी चाहिए कि जहां राजनीतिक दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जायें कि फौज का दखल देना पड़े या पडोसी देश अपनी स्वार्थों की रोटियां सेंकने में सफल हो जाये। भारत के पडोसी देशों के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामहिक निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। इन पडोसी देशों के नेता दो तरह के हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासारिक और अप्रासारिक के बीच भेदेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करने तो सभी पडोसी देश मिलकर विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इन पडोसी देशों के स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने की अपेक्षा है। भारत इस स्थिति में है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कघाने गालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में अक्सर सही-गलत वर्चा होती रहती है। हममें से अधिकांश लोगों ने वक्फ का नाम तो सुना है, लेकिन वह इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। वक्फ होता क्या है? किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है? और क्या मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के संविधान में तब्दीली की तोशिशों का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेट्स पर पड़ सकता है? चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड है। इसलिए हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बवसपे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत में इस्लाम की आमद के पाथ वक्फ के उदाहरण मिलने लगे थे। दिल्ली सल्तनत के वक्फ से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। मुगल शासन काल में यायः वही वाकिफ होते, और वक्फ कायम करते जाते। जैसे कई गदाशहों ने मस्जिदें बनवाईं, वो सारी वक्फ हुईं और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रहीं। इसके पश्चात 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक ट्रॉकर बनाने की बात उठने लगी। इस तरह 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नीति वक्फ का बोर्ड बना। ये एक द्रष्टव्य, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गईं। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद, इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1995 में या वक्फ बोर्ड एक्ट आया। 2013 में मनमोहन सरकार के समय इसमें नई संशोधन करके इसे पूरी तरह से तानाशाही रूप दे दिया गया।

